का अधिकतम प्रसार करने के लिए देश में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) जनवरी, 1994 के अंत तक देश के किस-किस राज्य में ऐसे कितने-कितने केंन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और आंठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ऐसे कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन केन्द्रों की स्थापना पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ड.) इस अवधि के पूरा हो जाने पर इन केन्द्रों में खाद्य प्रसंस्करण कला में प्रति वर्ष कुल कितने युवकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ड.) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना नहीं करता । तथापि मंत्रालय द्वारा एक योजना स्कीम लागू की जा रही है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है । योजना के अंतर्गत गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों सहित संयंत्र और उपकरणों की लागत को पूरा करने के लिए 2.00 लाख रु. तक का सहायता अनुदान दिया जाता है । योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मूल धनराशि/आवर्ती निधि के रूप में प्रत्येक केंद्र को एक बार अधिकतम 1.00 लाख रु० दिए जाते हैं । योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ लघु खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को चलाने और उनकी प्रबंध व्यवस्था करने का "प्रत्यक्ष" प्रशिक्षण देना है । 1992-93 में शुरू हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर जनवरी, 1994 तक 43 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जा चुकी है । उनका राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

बिहार . . .	3
हरियाणा . . .	2
हिमाचल प्रदेश . .	1
कर्नाटक . . .	3
मिजोरम . . .	6
तमिलनाडु . . .	1
उत्तर प्रदेश . .	19
प० बंगाल . .	8
कुल	43

इनमें से 15 केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है और शेष 28 केंद्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरण पर हैं और आशा है कि वे जल्दी ही काम करना शुरू कर देंगे । इसके अलावा, हाल में ऐसे और 74 केंद्रों को स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है और आशा है कि 1994 के अंत तक इनकी स्थापना हो जाएगी । आठवीं योजना के दौरान ऐसे 250 केंद्रों को 7.5 करोड़ रु० तक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । आशा है कि आठवीं योजना के दौरान इन प्रशिक्षण केंद्रों के मार्फत लगभग 30,000 युवक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

Joint Venture proposals in deep sea fishing

2818. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI MOOLCHAND MEENA:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether any Committee has been constituted by Government to look into Joint venture proposals in deep sea fishing;

(b) if so, the number of proposals cleared by the Committee during the current financial year;

(c) whether it is proposed to disband this committee; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) Joint venture proposals in deep sea fishing are considered by the Foreign Investment Promotion Board.

(b) Nine proposals for joint ventures in deep sea fishing have been cleared by the Committee during the current financial year 1993-94 (upto 28.2.1994).

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Policy to boost food processing units

2819. SHRI V. NARAYANASAMY:
SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has announced a new policy to boost food processing units in the country;

(b) if so, how many food processing industries have been started in India so far during 1993-94 and how many more such industries are proposed to be set up during the current financial year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) and (b) As per the new Industrial Policy of July, 1991 most of the Food Processing Industries has been granted high priority status. Moreover, most of the Food Processing Industries have been delicensed except the brewing and distillation of alcoholic drinks and those reserved for small scale industries. Consequently, the Food Processing Sector has attracted considerable investment. Till, January, 1994, 2471 Industrial Entrepreneur Memoranda involving an investmet of over Rs. 31,700 crores have been filed. Out of this 140 units have filed the second memoranda commencing commercial production till January, 1994. Since Food Processing Industries are both in the organised and unorganised sectors, information in regard to the number of Food Processing Industries Statewise set up during any particular year is not maintained Centrally While the Ministry of Food Processing Industries does not set up Food Processing Industries directly in any State, the Ministry under its Plan Schemes provides assistance to State Government Organisations, Joint Sector Companies, Cooperative Societies, Voluntary Agencies etc. for setting up|upgrading Food Processing Industries.

Strike by fishing workers' organisations

2820. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether fishermen and other fishing-workers' organisations went on a nation-wide strike on the 4th February, 1994 in protest against Government's deep sea fishing policy involving big multinational firms in deep sea-fishing to the detriment of small fishing companies;

(b) if so, what were their precise demands; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) Yes, Sir.